

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1179
दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत सुविधा

1179. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:
श्री रविन्द्र दलाराम वायकर:
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:
श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (1) क्या देश के विभिन्न राज्यों की सभी पंचायतों को इंटरनेट/ ई-पंचायत सुविधा प्रदान की गई है, यदि हाँ, तो विशेष रूप से दादरा और नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश और संभाजीनगर (औरंगाबाद) जिलों सहित महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (2) वर्तमान वर्ष सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान कितनी पंचायतों को इंटरनेट/ ई-पंचायत सुविधा प्रदान की गई;
- (3) संभाजीनगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र दादरा और नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (4) सरकार द्वारा उन गांवों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं जहाँ अभी तक इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य पंचायतों के कामकाज में सुधार लाना और उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। मंत्रालय ने पंचायत के काम जैसे आयोजना, लेखांकन और बजटन को सरल बनाने के लिए एक लेखांकन एप्लिकेशन ई-ग्राम स्वराज शुरू किया है। मंत्रालय ने विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ग्राम पंचायतों (जीपी) हेतु सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ ई-ग्राम स्वराज को भी एकीकृत किया है। अब तक, वर्ष 2024-25 के लिए 2,54,508 ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) तैयार की गई हैं और ई-ग्राम स्वराज में उपलब्ध हैं। वर्ष 2023-24 के लिए ई-ग्राम स्वराज के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति **अनुबंध-1** में दी गई है।

उच्च बैंडविड्थ क्षमता प्रदान करने, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं और बॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए, देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,55,000) को जोड़ने के लिए नेटवर्क बनाने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना लागू की जा रही है। भारतनेट परियोजना का मुख्य लक्ष्य पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। भारतनेट पर

सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार सूची अनुबंध-॥ में दिया गया है। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक सेवा तैयार बिंदु हो सकते हैं।

इसके अलावा, दिनांक 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत भारतनेट चरण-। और चरण-॥ के मौजूदा नेटवर्क को उन्नत किया जाएगा। शेष 42,000 ग्राम पंचायतों (लगभग) में नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा, 10 वर्षों तक संचालन और रखरखाव किया जाएगा तथा कुल 1,39,579 करोड़ रुपये की लागत से इसका उपयोग किया जाएगा। लगभग 3.8 लाख गैर-ग्राम पंचायत गांवों को उनकी संबंधित ग्राम पंचायतों की मांग के आधार पर कनेक्टिविटी प्रदान करने का प्रस्ताव है। बीएसएनएल को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। निविदा संबंधी गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं।

ख) ई-पंचायत परियोजना के तहत पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), दादरा और नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश द्वारा तैयार की गई और ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध कराई गई ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (जीपीडीपी) इस प्रकार हैं।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला		2024-2 5	2023-2 4	2022-2 3	2021-2 2	2020-2 1
महाराष्ट्र	27951	27750	27745	27799	27878	27876
छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)	871	868	862	867	866	863
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश	38	38	35	38	38	0
मध्य प्रदेश	23011	23001	23002	22988	22708	22801

इसके अतिरिक्त, मार्च 2019 से मार्च, 2024 तक तथा अक्टूबर, 2024 तक भारतनेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की कुल संख्या **अनुबंध -III** में दी गई है।

ग) महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर, दादरा और नगर हवेली तथा मध्य प्रदेश में भारतनेट का कार्यान्वयन निम्नानुसार है।

राज्य/जिला	चरण-। और चरण-॥ में नियोजित जीपी	चरण-। और चरण-॥ में एसआरजीपी	एबीपी में नियोजित जीपी
महाराष्ट्र	27689	24575	250
छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)	868	751	13
दादरा और नगर हवेली ज़िला	20	20	0
मध्य प्रदेश	17850	17850	5008

घ) गांवों/सरकारी संस्थाओं, स्कूलों, डाकघरों और निजी क्षेत्रों सहित ग्राम पंचायतों/ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं।

- I. इंटरनेट कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए भारतनेट अवसंरचना को टीएसपी/आईएसपी को बिना किसी भेदभाव के पट्टे पर दिया गया है।
- II. ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही संस्थाओं के लिए हाई-स्पीड डेटा कनेक्शन की मांग का पता लगाने के लिए बीबीएनएल/बीएसएनएल द्वारा उपयोगकर्ता मंत्रालयों/विभागों से संपर्क किया गया है।
- III. मांग पंजीकरण पोर्टल 'https://ruralfiber.bsnl.co.in' तैयार किया गया है और मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किया गया है।
- IV. बीएसएनएल ने जीपी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए फ्रेंचाइजी और राजस्व साझा भागीदारों को शामिल करने के लिए फ्रेंचाइजी प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) तैयार की है।
- V. ग्राम पंचायतों में नेटवर्क उपलब्धता में सुधार करना

1. दोषपूर्ण/क्षतिग्रस्त ऑप्टिकल फाइबर केबल की मरम्मत के लिए नियोजित रखरखाव एजेंसियों और फाइबर रखरखाव एजेंसियों की नियुक्ति की गई है।

संशोधित भारतनेट कार्यक्रम दिनांक 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, भारतनेट चरण- I और चरण- II के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन, शेष 42,000 ग्राम पंचायतों (लगभग) में नेटवर्क का निर्माण, 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव जिसके लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।

1. अनुबंध-1

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए पंचायत स्तर पर ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
1	आंध्र प्रदेश	13328	13296	13095	660	660	650	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2106	1449	0	0	0	25	25	22
3	असम	2662	2197	2191	191	191	191	30	27	27
4	बिहार	8176	8176	8057	534	534	528	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11655	11654	11249	146	146	145	27	27	27
6	गोवा	191	190	86	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14627	14591	13852	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6225	6220	5653	143	143	128	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3614	3545	81	81	80	12	12	12
10	झारखण्ड	4345	4345	4341	264	264	264	24	24	24
11	कर्नाटक	5953	5953	5936	238	232	183	31	31	28
12	केरल	941	941	940	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23012	23010	22700	313	313	309	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27833	27795	26528	351	351	346	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	0	0	0	0	12	6	3
16	मेघालय	6800	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	843	841	785	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1293	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6798	6798	6788	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13241	13223	11627	152	151	136	22	22	20

क्र.सं ं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों एवं समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ग्राम पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड ब्लॉक पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	ऑनबोर्ड जिला पंचायतें	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें
21	राजस्थान	11255	11251	11029	362	353	352	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	179	0	0	0	6	6	4
23	तमिलनाडु	12525	12525	12449	388	388	386	36	36	36
24	तेलंगाना	12769	12769	12758	540	540	490	32	32	32
25	त्रिपुरा	1178	1178	1176	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखण्ड	7795	7794	7773	95	95	94	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57754	57752	57621	826	826	817	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3225	345	345	336	22	21	21
कुल		263640	252104	245032	8659	6402	6224	650	640	624

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल जीपी/टीएलबी	सेवा के लिए तैयार जीपी/ सेवा के लिए तैयार बिंदु
1.	आंध्र प्रदेश	13327	12972
2.	अंडमान और निकोबार	70	81
3.	अरुणाचल प्रदेश	2108	1133
4.	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	42	41
5.	असम	2662	1634
6.	लक्ष्मीप	10	9
7.	बिहार	8054	8860
8.	लद्दाख	193	193
9.	छत्तीसगढ़	11648	9759
10.	पुदुचेरी	108	101
11.	गोवा	191	0
12.	गुजरात	14656	14559
13.	हरियाणा	6223	6204
14.	हिमाचल प्रदेश	3615	416
15.	जम्मू और कश्मीर	4291	1115
16.	झारखण्ड	4345	4649
17.	कर्नाटक	5953	6251
18.	केरल	941	1130
19.	मध्य प्रदेश	23011	18106
20.	महाराष्ट्र	27951	24778
21.	मणिपुर	3812	1479
22.	मेघालय	6832	696
23.	मिजोरम	843	535
24.	नागालैंड	1315	236
25.	ओडिशा	6794	7099
26.	पंजाब	13238	12807
27.	राजस्थान	11218	8997
28.	सिक्किम	199	54
29.	तमिलनाडु	12525	10295
30.	तेलंगाना	12771	10926
31.	त्रिपुरा	1192	772
32.	उत्तर प्रदेश	57702	47434
33.	उत्तराखण्ड	7795	2021
34.	पश्चिम बंगाल	3339	2958
कुल योग		268974	218300

अनुबंध -III

'ई-पंचायत सुविधा' के संबंध में दिनांक 03.12.2024 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1179 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध ।

भारतनेट के माध्यम से उपलब्ध कराये गये संचयी ब्रॉडबैंड कनेक्शन की संख्या
